भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1584

दिनांक 10 **फरवरी**, 2022

पीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन

1584. **श्री महाबली सिंह**:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की शुरूआत के बाद से इसके अंतर्गत अब तक प्रदान किए गए एलपीजी कनेक्शनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएमयूवाई के तहत विशेष रूप से बिहार के औरंगाबाद जिले में वर्ष और राज्य-वार निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(ग) उपभोक्ताओं को कितनी राजसहायता दी जा रही है;

(घ) उक्त योजना के तहत घरों को एलपीजी उपलब्ध कराने के बाद विशेष रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल उपभोक्ताओं की संख्या में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आई कमी का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा देश में घरों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए राज्य-वार विशेष रूप से बिहार में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) दिनांक 01.02.2022 की स्थिति के अनुसार, प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) ने 8.99 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी किए हैं जिसमें पीएमयूवाई चरण-I और उज्ज्वला 2.0 शामिल हैं।

(ख) पीएमयूवाई योजना के अंतर्गत कोई राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। दिनांक 01.02.2022 की स्थिति के अनुसार, पीएमयूवाई योजना के अंतर्गत ओएमसीज ने बिहार के औरंगाबाद जिले में 2.03 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किए हैं।

(ग) पीएमयूवाई के अंतर्गत नामांकित उपभोक्ताओं सहित सभी घरेलू उपभोक्ताओं को गैर राजसहायता मूल्य से रीफिल दी जाती है और लागू राजसहायता उनके पंजीकृत बैंक खातों में सीधे अंतरित कर दी जाती है। सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में घरेलू एलपीजी से संबंधित विभिन्न योजनाओं के लिए राजसहायता देने के लिए 11,895 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) नेटवर्क के अंतर्गत राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश (यूटीज) में राशन कार्ड धारकों/उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को पीडीएस मिट्टी तेल का वितरण करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश की होती है। संबंधित राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश वितरण के पैमाने और मानदंड पर भी निर्णय लेती हैं। तथापि, अन्य घटकों के साथ, एलपीजी की पैठ बढ़ने के साथ ही 11 राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश पीडीएस मिट्टी तेल मुक्त बन गए हैं।

(ङ) एलपीजी कनेक्शन जारी किया जाना एक सतत प्रक्रिया है और बिहार राज्य सहित पूरे देश में नए एलपीजी कनेक्शन संबंधी किसी भी अनुरोध को तत्काल रजिस्टर करने के लिए एलपीजी वितरकों को निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, देश के सभी घरों में एलपीजी कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाएं हैं जिसमें पीएमयूवाई के तहत जमानत रहित एलपीजी कनेक्शन, बाधारहित कनेक्शन, 5 किग्रा. सिलेण्डर, मौजूदा एलपीजी कनेक्शन धारक के लिए दूसरा कनेक्शन, पीएमयूवाई सहित नए कनेक्शनों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प, ई-सब्सक्रिप्शन वाउचर जारी करना, एलपीजी पंचायतों का आयोजन तथा राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को शामिल करते हुए जन जागरूकता अभियान चलाना शामिल है।

****